'अप्प दीपो भव'

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

वॉयस ऑफ बुद्धा

प्रकाशन तिथि- 31 दिसंबर, 2014

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, क्लॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 18 ● अंक 3 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 16 से 31 दिसंबर, 2014

परिसंघ की 17वीं महारैली सम्पन्न

पूरे देश से लाखों की संख्या में अधिकारी-कर्मचारी एवं बुद्धिजीवी रैली में हुए शामिल

सी.एल. मौर्य

8 दिसंबर, 2014 को लाखों की संख्या में दलित कर्मचारी, अधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के बैनर तले रामलीला मैदान, नई दिल्ली में एकत्रित हुए। प्रातः 10 बजे से ही रामलीला मैदान में लोगों का जमावड़ा शुरु हो गया और डॉ. उदित राज ने रैली में आए सभी लोगों को धन्यवाद दिया व उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ये लोग अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की बड़ी उम्मीद के साथ आज पूरे देश से आकर यहां इकट्ठा हुए।

भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री नितीन गडकरी, श्री सतीश उपाध्याय, श्री प्रभात झा, श्री विजय गोयल सहित अपना दल से सांसद अनुप्रिया पटेल एवं अन्य ने रैली में शिरकत की।

डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ ने कहा कि कर्मचारी एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की जिम्मेदारी समाज के लिए लड़ना है। जहां तक दलितों-आदिवासियों की सेवा करने का सवाल है, कर्मचारियों-अधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की भूमिका नेताओं से कम नहीं है। अन्य शब्दों में, दलित कर्मचारी नेताओं की तरह ही अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने शिक्षित लोगों से न्याय के लिए संघर्ष करने की ज्यादा उम्मीद की थी। यह अनुसूचित जाति/ जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ जो देश का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है की 17वीं महारैली है। अन्य संगठनों से इसका अलग अस्तित्व है क्योंकि यह रचनात्मक कार्यों में संलग्न है बजाय कि उच्च जातियों को गाली देकर अपने अस्तित्व को बचाये रखने के। हमारी जो भी प्रगति हुई है अधिकार से ही। अधिकार से विचारधारा भी पनपती है। अपनी इसी नीति के कारण अजा/जजा परिसंघ दलितों के लिए बहुत से अधिकार सुनिश्चित करा सका है। परिसंघ के संघर्ष के कारण ही तत्कालीन वाजपेयी की सरकार ने संविधान में 81वां, 82वां व 85वां संशोधन करके आरक्षण बचाया। इसके द्वारा सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं का ही समाधान नहीं किया गया बल्कि दिन-प्रति-दिन हो रहे दलितों पर अत्याचार के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी गयी। परिसंघ के कारण ही निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा अस्तित्व में आया।

इस समय परिसंघ के लोगों में भारी उत्साह का बड़ा कारण है कि नयी सरकार आयी है और वह जरूर कुछ करेगी। 2004 में यूपीए के नेतृत्व में बनी सरकार ने आरक्षण कानून बनाने से संबंधित बिल तुरंत ही पेश किया जो 2009 में पास भी हुआ लेकिन इसमें बहुत सी अनियमितताएं थी, उस समय सरकार ने इन कमियों को दूर कर एक मजबूत बिल पेश करने के उद्देश्य से इसे वापिस ले लिया। लेकिन यह यूपीए द्वितीय कार्यकाल में भी पास नहीं हो सका। हम उम्मीद करते हैं कि यह सरकार इस बिल को पास करेगी।

पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित दूसरा बिल 2012 में राज्यसभा में पास किया गया लेकिन लोकसभा में लटक गया। इस मांग को पूरा करने में भी सरकार को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आरक्षण लागू करने में बहुत सी खामियां हैं। हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पदोन्नति के संबंध में नकारात्मक निर्णय दिया है जिससे दलित कर्मचारी-अधिकारी प्रभावित हो रहे हैं और उनकी पदावनति शुरु हो गयी है। अनुसूचित जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को मजबूत बनाने से संबंधित बिल पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एमपावरमेन्ट के समक्ष है जो पास किया जा सकता है। अभी हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड रिसर्च और मेरिलेंड विश्वविद्यालय, अमेरिका ने संयुक्त सर्वे में पाया कि हर चौथा भारतीय छुआछूत का शिकार है। इन समस्याओं के अलावा सरकारी विभागों में ठेकेदारी प्रथा लागू होने से शोषण तेज हुआ है और आरक्षण भी समाप्त हुआ है, जिसे अतिशीघ्र रोका जाना चाहिए। सरकारी विभागों में बहुत कम भर्तियां हो रही है, इन विभागों में बढ़े हुए काम को करने के लिए अध्यापक, डॉक्टर, नर्स, सहायक, चपरासी, सलाहकार एवं एक्पर्ट आदि या तो ठेके पर अथवा अस्थायी तौर पर रखे जाते हैं, जिसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार दलित अभ्यर्थी अवसर से वंचित हो रहे हैं। औसतन ऐसे कर्मचारियों की संख्या 30 से 40 प्रतिशत तक सरकारी विभागों में पहुंच गयी है जहां आरक्षण से अभ्यर्थी वंचित हो रहे हैं। ऐसे अस्थायी कर्मचारियों को कुछ समय के बाद जब स्थायी करने की बात आती है तो दलित अभ्यर्थी के पास कार्य का अनुभव नहीं होने की वजह से अवसर से वंचित हो जाते है। इस प्रकार दलितों को दोहरा नुकसान हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अस्थायी एवं ठेके पर कर्मचारियों को रखते समय भी आरक्षण मिले। एक राज्य से बना हुआ जाति प्रमाण पत्र सभी राज्यों में मान्य होना चाहिए।

यूपीए की सरकार ने निजी क्षेत्र में आरक्षण देने पर विचार करने के लिए तीन समितियों का गठन किया था जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला और बाद में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ एक समझौता हुआ कि वे अनुसूचित जाति-जनजाति को विभिन्न क्षेत्रों, जैसे शिक्षा, रोजगार, व्यवसासय करने और नौकरियां पाने के लिए दलित नौजवानों को तैयार करेंगे। कुछ औद्योगिक इकाईयां अनुसूचित जाति-जन जाति के छात्रों को ट्यूशन, शिक्षा, प्रशिक्षण और उन्हें उद्यमी बनाने के लिए आगें आएंगें लेकिन इसका शायद ही जमीन पर कुछ हो सका हो। इस प्रकार हमारा समुदाय समाज की मुख्यधारा जैसे पूंजी बाजार, उद्योग, तकनीक, सेवा क्षेत्र, निजी शिक्षा, फिल्म, पत्रकारिता, आयात-निर्यात आदि में अभी भी इसकी भागीदारी लगभग शून्य है। इससे इस समुदाय को ही नहीं बल्कि देश की अखंडता व एकता को भारी खतरा है। इतनी बड़ी आबादी को समाज की मुख्यधारा से अलग रखकर कोई भी देश कैसे तरक्की कर सकता है? अमेरिका जैसे देश में भी अफरमेटिव ऐक्शन लागू है जो आरक्षण से भी ज्यादा है और वहां के वंचितों को सरकारी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में भी अवसर मिलता है।

+++

अजा/जजा परिसंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन, डॉ0 उदित राज रैली में उपस्थित जन समूह को सम्बोधित करते हुए।

इस अवसर पर डॉ0 उदित राज के दाएं मंच पर मौजूद दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, श्री सतीश उपाध्याय व बाएं केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी, आलेख मलिक, परमेन्द्र व डॉ0 इन्द्राज

डॉ0 उदित राज के पीछे खड़े सत्य प्रकाश जरावता, नाहर सिंह एवं बी.एल. बैरवा

कैमरे की नजर से महारैली की झलकियां

मंचासीन सांसद – श्री अर्जुनराम मेघवाल एवं विजय गोयल

मंच पर बाएं से जे.आर. हरनोटिया, सीमा राज, डॉ0 उदित राज, सतीश उपाध्याय एवं सांसद अनुप्रिया पटेल

मंच पर बाएं से नेतराम ठगेला, आर.के . कलसोत्रा, रोहित कुमार, हीरा लाल एवं सांसद छोटे लाल

बाएं से कमल कृष्ण मंडल, सपन हलदर, अनिल मेश्राम, डॉ0 अंजू काजल, डॉ. संदीप कुमार एवं गोपाल पहाड़िया

आन्ध्र प्रदेश परिसंघ का विशाल झुंड का नेतृत्व करते महेश्वर राज एवं जे.बी. राजू

बाएं से सांसद छोटेलाल, बलवंत चार्वाक, कर्मसिंह कर्मा, ब्रह्म प्रकाश, जगजीवन प्रसाद, एन.जे. परमार, आर.एस. मौर्य आदि

बाएं से एन.डी. राम, रवीन्द्र सिंह, कंवर सिंह एवं पीछे खड़े धनंजय सिंह एवं वाई. के. आनंद

25 लाख बनाम हजारों

डॉ0 उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष – अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, ने 8 दिसंबर 2014 को रामलीला मैदान, दिल्ली में आयोजित रैली में उपस्थित विशाल जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि लगभग 25 लाख अधिकारी एवं कर्मचारी जो अच्छे पढ़े-लिखे हैं और उनका कैरियर भी सुरक्षित है, वे समाज के लिए सांसदों व विधायकों से कहीं अधिक कर सकते हैं। ये सांसद एवं विधायक विभिन्न राजनैतिक पार्टियों में ज्यादातर पार्टी के मुखिया के इशारे पर कार्य करते हैं। क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए ज्यादातर पार्टी प्रमुख ही निर्णय लेते है। ऐसी स्थिति में हम सिर्फ राजनैतिक लोगों पर समाज की जिम्मेदार कैसे छोड़ सकते हैं और उनसे बड़ी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि सभी राजनैतिक लोग धोखेबाज एवं स्वार्थी हैं, बल्कि उनकी अपनी सीमाएं है। यदि वे अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालते हैं तो उन्हें इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इन राजनैतिक लोगों को पार्टी के द्वारा ही धन, वोटर एवं कार्यकर्त्ता उपलब्ध कराए जाते हैं और यदि पार्टी की नीतियों के विरूद्ध कोई काम करे तो ये सुविधाएं वापिस ले ली जाती हैं। ऐसे में इनकी मजबूती खत्म हो जाती है और दलित समाज भी साथ नहीं देता। यह उनके लिए बड़ी भयावह एवं अपमानजनक बात होती है कि वे अलग-थलग एवं प्रभावहीन हो जाते हैं। हमारा समाज अन्यों से भिन्न है क्योंकि यह स्वार्थी एवं कायर भी है। यदि उच्च जाति के राजनैतिक लोगों का अपमान होता है तो उनकी जाति सड़कों पर आ जाती है एवं उनके पक्ष में धरना-प्रदर्शन करते हुए अपना रोष प्रकट करती है, लेकिन क्या दलितों व आदिवासियों के नेताओं के साथ ऐसा कुछ होता है तो यह समाज कुछ करता है? उच्च जातियों की नेतृत्व वाली पार्टियों द्वारा दलित गतिविधियों की न केवल अनदेखी की जाती है बल्कि दलित राजनैतिक लोग अपने लोगों द्वारा भी छोड़ दिए जाते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि दलित राजनैतिक चिंतक समाज के लिए जो उनसे अपेक्षा की जाती है, नहीं कर रहे हैं। कुछ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करते हैं लेकिन असुरक्षा एवं जानकारी के अभाव में वे ऐसा नहीं कर पाते हैं।

दलित अधिकारी व कर्मचारी देश में लगभग 25 लाख हैं और उन्हें पूरी जानकारी भी है और 60 साल तक सेवा में रहने की गारंटी भी है, वे समाज के लिए इन राजैनैतिक लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक कर सकते हैं। इनकी संख्या भी समाज में अच्छी-खासी है। उनके पास धन, योग्यता और समय पर्याप्त रूप से समाज को निर्देशित करने के लिए होता है। अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ उपरोक्त तथ्यों में विश्वास ही नहीं करता बल्कि इसके द्वारा ऐसे प्रयोग सफल भी रहे हैं। आरक्षण विरोधी आदेशों की वापिसी के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों ने ही मूल रूप से संघर्ष किया। यदि कोई कर्मचारी कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता तो यह सिवाय बहाने के कुछ नहीं है, क्योंकि यह साबित हो चुका है। 80 के दशक के बाद समाजिक न्याय का संदेश पूरे उत्तर भारत में पहुंचा तो इसे पहुचाने वाले दलित कर्मचारी-अधिकारी ही थे। अब समय आ गया है कि लाखों कर्मचारी समाज को जागृत करने के लिए आगे आएं। ऐसा करने में कोई खतरा भी नहीं है क्योंकि यह सबसे सरल माध्यम है। वे अपने ज्ञान व धन का थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर दें तो समाज जागृत हो जाएगा। हमारा समाज बहुत बड़ा है और सही मकसद के साथ उन्हें एकजुट करने से हमारा सम्मान, अधिकार व शासन-प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। ✦✦✦

सम्बोधित करते हुए महेश्वर राज

तरसेम सिंह – पंजाब

आर.के. कलसोत्रा – जम्मू

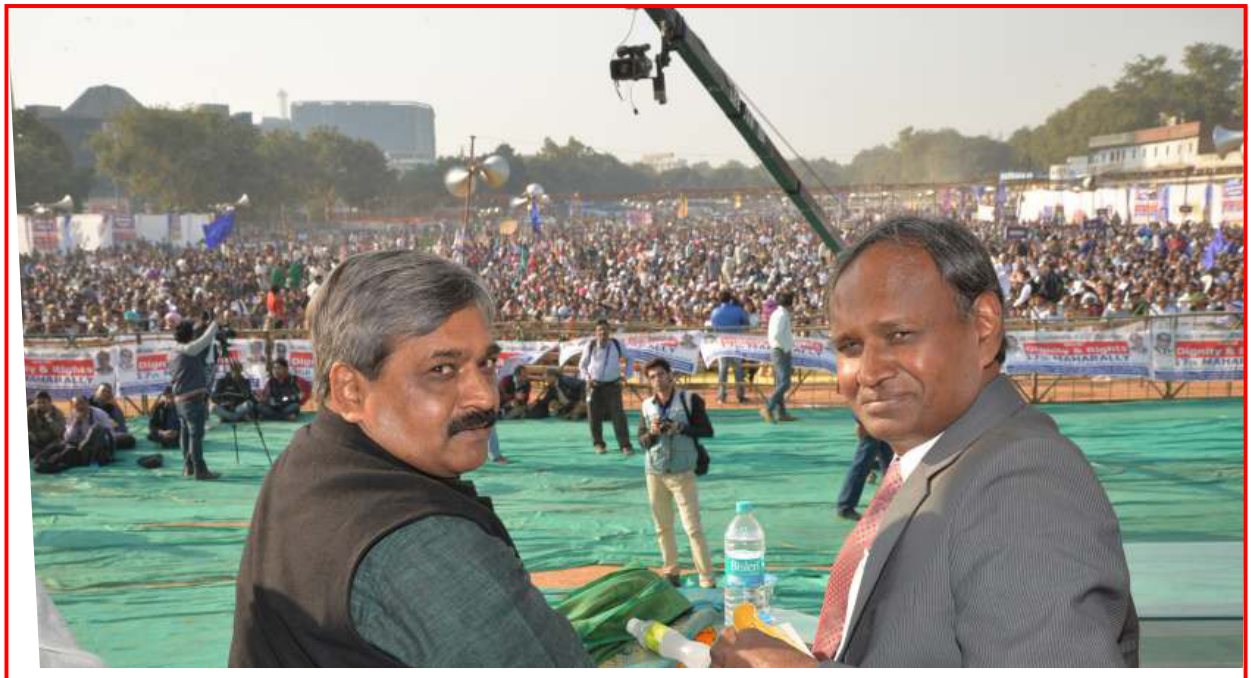

रैली का अभिवादन करते हुए डॉ0 उदित राज के साथ दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय

अधिकार एवं सम्मान रैली सफलतापूर्वक संपन्न

सतप्रकाश प्रयासी

भारत एक बहुभाषी, बहुजातीय, बहुधर्म, बहुवेशभूषा, बहुसभ्यता एवं संस्कृति वाला देश है। एक तरफ वसुधैव कुटूम्बकम की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ जातीय भेदभाव छुआछूत इस देश का पीछा नहीं छोड़ता है। इसकी विशेष वजह यह है कि यह चंद चालाक लोग अपनी चालाकी से एक बहुसंख्यक समुदाय को हमेशा अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, अपनी जी-हुजूरी करने वाला देखना चाहते हैं। वह हमेशा एक लकीर खींच कर रखना चाहता है। वह नहीं चाहता कि दलित पिछड़ा समाज उसके बराबर खड़ा हो या उसके बराबर तरक्की करे। वह यही चाहता है कि शोषित पीड़ित वर्ग अनादि काल तक सम्मान और अधिकार से वंचित रहे। इसलिए यह परंपरा वह हमेशा कायम करना चाहता है। यद्यपि भारतीय संविधान निर्माता डॉ. अम्बेडकर ने एक सपना देखा था कि यह देश आने वाले समय में इन दलितों-पिछड़ों का समानता प्रदान कर देगा और यह दबा-कुचला समाज भी देश की उन्नति में अपनी उन्नति को समझते हुए सम्मान से जीने लगेगा।

8 दिसंबर, 2014 को देश की राजधानी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली हुई। परिसंघ की यह रैली सामान्य तरह की रैली नहीं थी बल्कि यह विशिष्ट रैली हुई। फिर से उसी उत्साह तथा जोश के साथ एक बार फिर से लाखों की संख्या में लोग अपने अधिकारों एवं सम्मान के लिए रामलीला मैदान की ओर उमड़ रहे थे। देखते ही देखते रामलीला मैदान खचाखच भर गया और चारो ओर लोग ही लोग नजर आ रहे थे। बड़े-बड़े नेताओं ने इसे महारैली नहीं महारैला कहकर संबोधित किया। देशभर से ढोल नगाड़े बजाते हुए लोग आ रहे थे। हाथों में पदोन्नति में आरक्षण, निजी क्षेत्र में भागीदारी, समान शिक्षा, समान अधिकारों की मांग को लेते हुए झंडों को लेकर लोग आ रहे थे। उनके साथ साजबाज थे। रामलीला मैदान इन नारों से गूंज रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट से बड़े हुजूम के साथ हजारों की संख्या में लोग रामलीला मैदान में आ रहे थे। डा अम्बेडकर की जय के नारों से मैदान गूंज रहा था। एक तरफ जब हुजूम आ रहा था तो दूसरी तरफ अलग-अलग प्रांतों के नेता आ रहे थे। प्रत्येक राज्य के लिए अलग पांडाल था।

बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के बड़े-बड़े पोस्टरों से अहसास हो रहा था कि अब फिर से एक बार दलितों में पढ़ा-लिखा विवेकशील समाज खुले आसमान की ओर अपनी निगाहें टिकाए मानों यह कह रहा हो कि वह अब इसके बाद से अपने स्वाभिमान और अपना अधिकारों को लेकर रहेंगे।

राजधानी से अनेकों दिग्गज नेतागण भी इसमें आए। इसमें दर्जनों दलित सांसद मंत्रीगण आए। यही नहीं अनेकों आईएस अधिकारी हजारों की संख्या में क्लास वन अधिकारी इस रैली में शामिल होने आए थे। ऐसा लग रहा था क्लास-1 अधिकारी भी कहीं न कहीं उच्च पदों पर होने पर भी अपने-अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। वे संकल्पित दिखाई दे रहे थे कि वे अब अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि इतनी बड़ी रैली को देखकर हम यह कह सकते हैं कि आने वाला समय में दलितों-वंचितों को उनके अधिकार और सम्मान अवश्य मिलेगा। गैरबराबरी समाप्त होगी और शोषितों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दलितों के हितों के प्रति अत्यधिक सजग एवं संवेदनशील है। उन्होंने डॉ. उदित राज को कहा कि उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी और उनका समर्थन करते हुए उसे पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। पढ़े-लिखे इस समाज को आज यहां एकत्र कर यह साबित होता है कि यह पढ़ा-लिखा अब चुप नहीं बठेगा और अपने अधिकार एवं सम्मान के लिए लाखों की संख्या एकत्र होकर क्रांति ला सकता है। उन्होंने कहा कि जितनी भी मांगे यहां उठी हैं सरकार उनके प्रति सजग है और इन पर हमारी सरकार विचार करेगी और इनको पूरी करने की पूरी कोशिश करेगी।

इस अवसर पर दलित नेता एवं मंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल ने भी रैली को संबोधित किया और कहा कि परिसंघ द्वारा उठाई गई सभी मांगों का वे समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि वह भी सरकार से इन मांगों को पूरा करने के लिए संसद में आवाज उठाएंगे।

अपना दल की नेता व सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इस देश में समाजिक असमानता को कम करने लिए अभी तक कोई ठोस कार्यनीति तैयार नहीं की गई। दलित समाज पर अत्याचार, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं कम होने की बजाय बढ़ रही हैं। सरकार में कई वर्षों से कई पद खाली पड़े हैं। उनकों भरने के लिए कोई ठोस पहल नहीं हो रही है। ऐसे में इस समाज को एकत्र तो होना ही पड़ेगा। परिसंघ के चेयरमैन डॉ. उदित राज ने अपने ओजस्वी भाषण में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया।

समान शिक्षा, निजी क्षेत्र में आरक्षण आदि

उन्होंने समतामूलक सम्मान प्राप्ति जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखी। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश के परिसंघ के विभिन्न नेताओं ने अपनी-अपनी बात रखी। इसमें परिसंघ के महासचिव श्री विनोद कुमार, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नाहर सिंह, डॉ. धनंजय, श्री रवीन्द्र आदि नेता शामिल थे। दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी में आयोजित इस रैली में दिल्ली के लगभग सभी क्षेत्रों के परिसंघ से जुड़े कार्यकर्ता इसमें आए। परिसंघ अपने संकल्पों के प्रति अत्यधिक दृढ़ एवं मजबूत नजर आया। डॉ. उदित राज ने इस बात को बड़े जोरदार तरीके से उठाया कि यदि इस लाखों की संख्या वाली रैली से सरकार से हमें अपना अधिकार नहीं मिलता है, हमें अपना सम्मान नहीं मिलता है तो हमें आने वाले समय में कराड़ों की संख्या में भी शामिल होना पड़ेगा, तो हम होंगे। पदोन्नति मेंआरक्षण का मुद्दा भी रैली में बड़े जोरों पर था। परिसंघ के नेताओं का मानना है कि कई पद खाली पड़े हैं जिनमें पदोन्नति की जा सकती है। परंतु सरकारों की मंशा साफ नहीं है। इसलिए ये पद जानबूझकर नहीं भरे जा रहे हैं। सरकार कहीं न कही संविधान की अवहेलना कर रही है। उपेक्षित दलित समाज को कितना इंतजार करना पड़ेगा। दलितों-पीड़ितों-शोषितों की हिस्सेदारी क्यों नहीं अमेरिकी समाज जैसी हो जाती। अमेरिका में सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो कोई भी क्षेत्र हो उसमें ब्लैक की भागीदारी अवश्य होती है बिना ब्लैक की भागीदारी के गोरे कोई फिल्म तक नहीं बना सकते। अमेरिका का इतिहास भी यही बताता है कि जब ब्लैक पर ज्यादा अत्याचार हुआ तो लामबंद हुए और उन्होंने गोरों केखिलाफ एक जंग छेड़ी जिसका परिणाम आज हर क्षेत्र में उनकी पूरी भागीदारी है। दुनिया के कई देशों का इतिहास भी यही दोहराता है कि समाज को एक होकर अपने सम्मान और अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए।

यह रैली निःसंदेह एक सफल रैली रही है। इसलिए अब सरकारों को चाहिए कि दलित-शोषित को लाचार या कमजोर न समझे। दलितों-शोषितों ने बड़े ही अभावों में कमोबेश थोड़ा बहुत शिक्षा ग्रहण कर ली है। वह अब समझ गया है कि संविधान ने उसके लिए क्या क्या दिया है जिसे उसे अब हासिल करके रहना है। अब वह सोच रहा है कि वह इस बार चूकेगा नहीं। आखिर कब तक असमानता कायम रहेगी। इसका खात्मा कब होगा। इसके लिए एक चिंतन उभरने लगा है। समाज की उपेक्षा करना समाज के साथ नांइसाफी अब वह बर्दाश्त नहीं करेगा।

+++

मीडिया नहीं करता दलितों की बात

डॉ. नाहर सिंह

जिस प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के आवाहन पर 8 दिसंबर, 2014 को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में देश के कोने-कोने से दलित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने एकत्रित होकर सरकार को बताने का प्रयास किया कि देश का दलित वर्तमान समय में अगर किसी राजनेता का नेतृत्व स्वीकार करता है तो केवल एकमात्र दलित नेता डॉ. उदित राज को अपना नेता स्वीकार करता है क्योंकि राजनीति में आने से पहले तथा सांसद बनने के बाद अगर दलितों की किसी ने बात की या उनके किसी भी सरोकार को स्वीकारा तो केवल एकमात्र नाम सामने आता है। आज देश की राजनीति में विभिन्न राजनीतिज्ञ दलों एवं क्षेत्रीय पार्टियों में बहुत से दलित ऐसे समय में संघर्ष किया जब वह भारतीय राजस्व सेवा को छोड़कर दलित आंदोलन में कूद पड़े तथा सड़क से लेकर संसद तक दलितों की आवाज को पहुंचाया।

एक समय था जब कार्मिक विभाग, भारत सरकार ने दलित कर्मचारियों के विरूद्ध पांच आरक्षण विरोधी आदेश जारी कर दिए थे लेकिन डॉ. उदित राज के संघर्षो ने उनमें से तीन अध्यादेशों को वापस कराने में अहम भूमिका निभाई। देश की राजनीति में एक समय ऐसा आया जब ऐतिहासिक रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल के गठन को लेकर आंदोलन चरम पर था। लेकिन उस लोकपाल के गठन में दलितों की कोई भूमिका नजर नहीं आ रही थी। अगर उस समय डॉ. उदित राज दलितों के लिए आरक्षण की बात उस लोकपाल बिल में नहीं करते तो देश प्रतीत हो रहा था कि 8 दिसंबर की महारैली भारतीय मीडिया में इतिहास रच देगी लेकिन मीडिया के विभिन्न चैनलों में मात्र कुछ अंश दिखाए गए वो भी दलित रैली के बजाय इसे बीजेपी की रैली करार दिया गया। इस अवसर पर डॉ. नाहर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली इकाई ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली प्रदेश की तरफ से जब भी इस प्रकार का आयोजन दिल्ली अथवा दिल्ली से बाहर आयोजित किया जाता है तो दिल्ली इकाई के अधिकारी एवं कर्मचारीगण अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर डॉ. उदित राज जी के हाथ मजबूत करेंगे और अपने अधिकारों एवं सम्मान की लड़ाई जब तक लड़ते रहेंगे तब तक सरकार दलितों की उत्थान के लिए संसद में उचित बिल पास कराकर कार्रवायी नहीं करती है।

+++

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

दलितों को किसी भी राजनैतिक दल पर भरोसा नहीं

डॉ. नाहर सिंह

देश के इतिहास में आजादी से लेकर आज तक देश के दलितों का जितना उत्थान होना चाहिए था वह अभी तक किसी भी तरह दिखाई नहीं देता, चाहे वह सरकारी सेवा का क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र या फिर सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक भागीदारी की बात हो। निजी तौर पर पिछले कई चुनावों में राष्ट्रीय दलों के चुनावी घोषणा पत्रों का अध्ययन करने के बाद अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देश में जब से आरक्षण लागू हुआ है तब से उच्च वर्ग को लग रहा है कि दलित उनका हिस्सा छीन रहे है, जब कि ऐसा नहीं है। साथियों यदि शरीर के किसी भी हिस्से में बीमारी हो तो वह भाग कमजोर हो जाता है जिसे हम आमतौर पर स्वस्थ नहीं कह सकते, अर्थात् यदि समाज का एक वर्ग कमजोर हो तो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता।

विभिन्न राजनैतिक दलों में दलित वर्ग की भागीदारी केवल आरक्षण के आधार पर तो है लेकिन नीतियों को बनाने में कहीं पर नजर नहीं आते, जबकि असली क्रियान्वयन वही व्यक्ति पहले करते हैं। अगला प्रश्न यह आता है कि जिस प्रकार से सरकार ने सरकारी सेवाओं में निचले स्तर पर भर्तियां बंद कर ठेकेदारी प्रथा का शुभारम्भ किया है उससे बेरोजगारी को ही बढ़ावा नहीं मिल रहा अपितु सरकारी सेवाओ में हिस्सेदारी को कम किया जा रहा है। अगर कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि समूह 'घ' से लेकर समूह 'क' तक के पदों पर निर्धारित संख्या के अनुपात में भी पदों को नहीं भरा जाता है, केवल टालने के लिए या तो विज्ञापन दे दिया जाता है या फिर लम्बे समय तक उस प्रक्रिया पर काम नहीं किया जाता। जब तक राजनैतिक दल सत्ता में आने के बाद अपनी कथनी और करनी में अंतर करते रहेंगे तब तक देश के दलित केवल तुरुप के पत्ते की तरह ठ्ये जाते रहेंगे।

दूसरा प्रश्न यह है कि विकास के कार्यों में जैसे निर्माण, सफाई, रख-रखाव आदि कार्यों में अन्य वर्ग के लोगों की भागीदारी न के बराबर है लेकिन उसके उपयोग की जब बात आती है तो वह उसके लायक नहीं होता। उदाहरण के लिए एक दलित किसी मंदिर के निर्माण में तो काम कर सकता है लेकिन पुजारी बनने की जब बात आती तो उसका प्रवेश वर्जित है। साथियों, अगली बात निजी क्षेत्र में भागीदारी की करता हूँ जहाँ पर केवल शत-प्रतिशत सामान्य वर्ग के लिए ही स्थान आरक्षित होते हैं। किसी भी दलित के लिए कोई आरक्षण की सुविधा या सरकार की तरफ से कोई ऐसी नीति नहीं बनाई गई कि दलितों को निजी क्षेत्र में कार्य करने की सुविधा मिल सके। आज केंद्र की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ काम कर रही है इसलिए उनके पास दलितों की बात करने या उनके उत्थान के लिए कोई बिल संसद में पेश नहीं कर पा रही, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलितों के प्रति कितनी गंभीर है। अगर दलित नेताओं की बात आती है तो बहुत से दलित नेता हर राजनैतिक दलों में मिल जायेंगे लेकिन डा. उदित राज जिनके सानिध्य में अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के अखिल भारतीय परिसंघ को एक बेहतर दिशा मिल रही है जिसका एक उदाहरण 8 दिसंबर, 2014 को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में लाखों अधिकारी तथा कर्मचारियों ने पहुंचकर सरकार को बता दिया कि आज भी डॉ. उदित राज सांसद के रुप में ही नहीं अपितु दलितों के एक मात्र मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। यदि सरकार समय रहते दलितों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देती तो देश का दलित किसी भी राजनैतिक दल को महत्व नहीं देगा तथा एकजुट होकर एक नए दल के रूप में राज्यों तथा संसद में किसी भी दल को चुनौती देने की ताकत रखते हैं। अंत में कहना चाहूँगा कि यदि दलितों को सही सम्मान जो भी दल देगा वही देश पर शासन करेगा।

+++

अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस की शुरुआत सुशासन दिवस के रूप में

श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की हमने शुरुआत की है। उत्तर पश्चिम लोक सभा क्षेत्र के सांसद, डॉ0 उदित राज जी ने आज अपना पूरा दिन अपने लोक सभा क्षेत्र में बिताया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व किया और स्थानीय निकायों द्वारा किए जा रहे सफाई के कार्य का निरीक्षण व स्थानीय मुद्दों को नजदीकी से समझा। नीति निर्माण में भागीदारी हेतु भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया।

जौंती गांव में स्वच्छता अभियान का नेतृत्व एवं प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन

सबसे पहले माननीय उदित राज जी ने अपने द्वारा 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' के अंतर्गत गोद लिए गए जौंती गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ लोगों से मुलाकात की और उन्होंने स्वच्छता अभियान में सहयोग करने और अपने गांव के समुचित विकास में योगदान देने हेतु वहां के निवासियों से अपील किया। वहां पर उन्होंने गांव के नौजवानों के लिए एक 'प्रशिक्षण केन्द्र' का उद्घाटन किया। उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा घरेलू उद्योग विश्व प्रसिद्ध है, जिसे आर्थिक विकास हेतु प्रोत्साहित करने की जरूरत है। गांव के लोगों को नई-नई तकनीक सीखकर इसे अपनी पैतृक कला से जोड़कर इसे नया रूप देने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार की नीतियों जैसे - प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि वे गांवों को हाईटेक देखना चाहते हैं और इसके लिए सभी को कठिन मेहनत की जरूरत है। उन्होंने जर्मनी के एक गांव का उदाहरण देते हुए कहा कि तकनीक के प्रयोग के मामले में वहां के गांव किसी भी हालत में शहरों से कम नहीं हैं। उन्होंने जौंती गांव के निवासियों से अपील किया कि वे अपने बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा दें और शिक्षा को यथोचित महत्त्व दें। उन्होंने कहा कि बिना शिक्षा के हम अपने समाज और अपने गांव का विकास नहीं कर सकते।

डॉ0 उदित राज ने मुंडका में 40 करोड़ की लागत वाले भूमिगत जलाशय परियोजना का उद्घाटन किया

उसके पश्चात् डॉ0 उदित राज जी मुंडका पहुंचे जहां पर उन्होंने तीन महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं - (1) मुंडका के चारो ओर लगभग 464 लाख रूपये की लागत वाले फिरनी रोड, (2) लगभग 118 लाख रूपये की लागत वाले मुंडका-रनहोला रोड और (3) 40 करोड़ रूपये की लागत वाले भूमिगत जलाशय, जिसकी क्षमता लगभग 6.5 करोड़ लीटर की होगी, का उद्घाटन किया। इस जलाशय से क्षेत्र के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा, जिनमें हिरनखोदनी, निर्वाल, टीकरी, बाबा हरिदास कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी मुंडका, मुंडका औद्योगिक क्षेत्र आदि क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलेगा।

डॉ0 उदित राज जी ने मुंडका में जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटें। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि जिन परियाजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, ये लगभग एक साल के अंदर पूरी हो जाएंगीं। उन्होंने कहा वे तेज कार्यशैली में विश्वास रखते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का निराकरण हो सके। इस अवसर पर पार्टी के अन्य गणमान्य लोगों के अलावा पूर्व महापौर मास्टर आजाद जी भी उपस्थित थे।

मुशासन दिवस के अवसर पर स्कूल के वार्षिक समारोह में शामिल हुए

इसके पश्चात वे किराड़ी स्थित तुला राम पब्लिक स्कूल पहुंचे, जिनका वार्षिक समारोह 'सुशासन दिवस' को समर्पित था। यहां पर डॉ0 उदित राज जी ने विलक्षण उपलब्धि प्राप्त किए स्कूली बच्चों को पुरस्कार वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने अध्यापकों को समाज की जमीनी सच्चाई के नजदीक आने की अपील की ताकि वे बच्चों को और अच्छी शिक्षा दे सकें। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं आज हम 'सुशासन दिवस' क्यों मना रहे हैं? हमें सीखना है कि हम किस प्रकार का व्यवहार करें कि हमारे समाज में शांति आए और सभी लोग स्वाभिमान से जी सकें। बच्चे ही भविष्य में हमारे समाज का नेतृत्व करेंगें, इसलिए उनके पालन-पोषण में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुलानपुरी अंडरपास का उद्घाटन

डॉ0 उदित राज जी ने रेलवे क्रांसिंग के नजदीक सुल्तानपुरी में अंडरपास का उद्घाटन किया। इस अंडरपास के बनने में डॉ0 उदित राज जी का अथक प्रयास रहा है। उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इसे पूरा करने में अभी बहुत कुछ करना है, उन्होंने जो वायदे किए हैं, उन्हें करना ही पड़ेगा। डॉ0 उदित राज ने कहा कि इसके लिए वे लगातार अधिकारियों के सम्पर्क में रहेंगें।

अंत में डॉ0 उदित राज ने कबीर जन कल्याण मंच रोहिणी के वार्षिक समारोह में भाग लिया। इसके अलावा उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर बापू पार्क - मंगोलपुरी में बच्चों के लिए प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम, नागलोई में वार्षिक नागरिक सम्मान समारोह, गीता रतन जिंदल पब्लिक स्कूल में वार्षिक समारोह, पीतम पुरा में नेत्रहीनों के लिए सहायता शिविर, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर मंगोलपुरी में 'सायं सांस्कृतिक कार्यक्रम' आदि में भाग लिया। +++

डॉ0 उदित राज ने संसद में दलितों के चार मुद्दे उठाए

संसद का शीतकालीन सत्र 24 नवंबर, 2014 से 23 दिसंबर, 2014 तक चला। कुल 22 दिन संसद की कार्यवाही चली। इस दौरान डॉ0 उदित राज जी ने 32 सवाल संसद में पूछे और 6 बार विभिन्न मुद्दों पर भाषण दिया। जिनमें से ज्यादातर मुद्दे दलितों एवं गरीबों से संबंधित रहे। उन्होंने स्पेशल कांपोनेंट प्लान एवं ट्राइबल सब प्लान का मुद्दा संसद में उठाया। उन्होनें वित्त मंत्री महोदय से आग्रह किया कि अगले बजट में ऐसी कोई व्यवस्था जरूर की जाए जिससे कि दलितों के विकास के लिए राज्य सरकारों को दिया गया अनुदान अन्य मदों में न खर्च किया जा सके। दलितों एवं गरीबों को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के 38 साल पहले (1970-1976) में प्लाट एवं कृषि हेतु भूमि आबंटित की गयी थी लेकिन उन्हें अभी तक भूमिधरी अधिकार नहीं मिल सके हैं, यह मुद्दा भी संसद में उन्होंने उठाया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो आरक्षण की अवलेलना करने में अग्रणी रहा है, उसके विरुद्ध आवाज उठाते हुए डॉ0 उदित राज जी ने कहा कि भर्तियों के समय यहां पर आरक्षण के मानकों को नहीं अपनाया जाता। उन्होंने 2003 में 164 भर्तियों का उदाहरण देते हुए बताया कि उसमें आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यद्यपि ऐसे संस्थानों में सरकार का हस्तक्षेप कम होता है लेकिन फिर भी उन्हें नियमों को ताख पर रखकर आरक्षण की अहेलना करने का कोई अधिकार नहीं है। एक राज्य का जाति प्रमाण-पत्र अन्य राज्यों द्वारा सरकारी नौकरियों व शिक्षा सहित अन्य कार्यों में मान्य नहीं है। इस मुद्दे को संसद में उठाते हुए उन्होंने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली के बाहर से आने वाले लोगों को दिल्ली में आरक्षण से वंचित किया जाता है। फरवारी 2013 में सुप्रीम कोर्ट एवं मई 2013 में दिल्ली सरकार ने भी आर्डर जारी किया था कि दूसरे राज्यों से आने वालें दलितों को जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर अवसर दिया जाना चाहिए इसके बावजूद उन्हें मना किया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली में एमसीडी में टीचर्स की भती की गयी थी, जिसका परिणाम 5 दिसंबर को आया, जिसमें उन्हें आरक्षण से वंचित रखा गया। उन्होंने शहरी विकास मंत्री से आग्रह किया कि वे दिल्ली के राज्यपाल से कहकर उपरोक्त आर्डर पा पालन करवाते हुए इन्हें अवसर दिलवाएं। उन्होंने एक अतारांकित प्रश्न के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री से प्रश्न किया कि जे.ई.ई. परीक्षा में दलित अभ्यर्थियों को एक से अधिक अवसर क्यों नहीं दिया जाता? यदि नहीं दिया जाता तो इसके बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है? हालांकि जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि अभी दो से अधिक अवसर दिए जाने का कोई विचार मंत्रालय का नहीं है। एक अतारांकित प्रश्न के मध्यम से उन्होंनें खान मंत्री से पूछा कि नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लि. (नाल्को) अजा/जजा के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, इनमें से उच्च पदों पर कितने अधिकारी हैं? इसका जवाब देते हुए खान राज्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान में नालकों में जीएम/कार्यकारी निदेशक/सीएमडी जैसे पदों पर कोई भी अधिकारी एससी/एसटी/ओबीसी से नियुक्त नहीं है।

लोक सभा में आरक्षित कोटे से 131 सांसद चुनकर आते हैं। डॉ0 उदित राज जी ने सरकार में शामिल होने के बावजूद जिन प्रश्नों को उठाया, उन्हें उठाने की ज्यादा जिम्मेदारी विपक्षी पार्टियों के दलित सांसदों की बनती थी। दलित समाज को देश के विभिन्न क्षेत्रों से चुने गए अन्य 130 सांसदों से सवाल करना चाहिए कि वे आरक्षण की बदौलत जीतकर संसद में पहुंचकर क्या कर रहे हैं? अगर सभी ने एक-एक भी दलितों से संबंधित मुद्दा सदन में उठाया होता तो कम से कम 130 मुद्दे और होते। डॉ0 उदित राज द्वारा संसद में दिया गया विस्तृत भाषण व पूछे गए प्रश्न विस्तृत रूप से 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के अगले अंक में प्रकाशित किए जाएंगें। +++

Dr. Udit Raj worships Buddha at the BHU

Dr. Indu Choudhary

Varanasi 20th December, 2014. An Interdisciplinary International Seminar on Buddhism, Culture\Literature & the Constitution of India organized by the Department of English, Banaras Hindu University at R.K. Hall on 20th December, 2014 where Dr. Udit Raj, Hon'ble Member of Parliament was invited as Chief Guest, Ven. Prof. Lobsang Norbu Shastri was the Guest of Honour along with Dr. B. P Ashok (PPS), Dr. R. C. Gautam (Professor of Hindi), Prof. K. M. Pandey, HoD & Chairman of the Seminar welcome the guests. Dr. Indu Choudhary, Convener apprised the participants about the contribution of Dr. Udit Raj, JNU Alumni, in raising the issues faced by the underprivileged people in the Parliament of the country and resolving many of them. He launched a vigorous campaign in 2006 for seeking reservation for backward sections of people in institutions of higher education. Dr. Udit Raj is an international figure and also a prolific writer. He played an important role in the rollback of four year under-graduate program of Delhi University. Addressing the audience, Dr. Udit Raj quoted examples from day to day life and his own personal experiences. He said Buddhism has appeared to be an alternative as well as a reformative platform for Dalits to refurbish their caste identity imposed on them and to launch reformative plans and projects in order to remove casteism and untouchability. As a sixth century religious belief before Christ, Buddhism diagnosed the root of human existentialism and formulated curative theories and practices. It paved utilitarian and non-violent ways (which Gandhiji too followed) for the removal and redemption of cruelty, violence, hatred, pains, sufferings and other social ailments, as has been faced by human society from time to time. As the first social revolutionary of India, we find Lord Buddha as the embodiment of theory and praxis. If there was Panini, there too was Chandragomin, and if there were Katyayana and Patanjali, there too were Jayaditya and Jinendrabuddhi and Purushottamdasa and alike hailing from Buddhist tradition during the Nalanda period.

Friends, it is now time to realize and recollect how Buddhism has been the enlightening and enduring principle of our historical progress and, as Indians, we should take pride in such advanced social and religious philosophies which the western world still craves for to take refuge in. Ambedkar philosophy had roots in Buddhism and mission to make the Indians realize that a social philosophy affirming a life of liberty, equality and fraternity cannot be found anywhere but here in Buddha's Bharat alone.

I think the present seminar on Buddhism, Literature/Culture and the Constitution of India is a timely reminder to our ignorance of the relevance of Lord Buddha in our times. Dr B.R. Ambedkar understood the humanitarian forces of Buddhism and therefore embraced it on 14 October, 1956 at a place called Deeksha Bhoomi in Nagpur. In Buddhism, he found a rationalized faith embedded with social equality, non-violence and social service that can replace 'faith in god' with 'faith in humanity.' According to Ambedkar, Social Buddhism provides there things - Understanding, Equality, and Love. 'Understanding' to remove superstition and supernaturalism and to have correct view; 'Samata' or equality to hold all beings equal and respectable; and 'Karuna' and love to any one in crises.

In our times, Ambedkar stands as a towering intermediary between Dalits and Buddhism. Apart from being an architect of our Constitution, Ambedkar was an ambassador of school and university education, a pioneer of development of science, law and commerce. The schools and colleges established by him are testimony to this. With all these, I wish a grand success to the seminar and strongly believe that it would come up with some strategies and solutions for new transformation of Dalits in general and India in particular. Dr. Indu Choudhary greeted Dr. Udit Raj with a memento of Lord Budhha. Prof. K. M. Pandey and Prof. G.C. Behera gave vote of thanks with the promise from Dr. Udit Raj that he will be coming again when the next seminar is organized by the Department. +++

Tamilnadu Confederation Unit declared

New Delhi, 22.12.2014: At the conclusion of one-day Rally organized by All India Confederation of SC/ST Organizations, Dr. Udit Raj, Ex-IRS, Member of Parliament and National Chairman of the Confederation, nominated following important office-bearers against the posts mentioned against their names for Tamilnadu State Unit of the Confederation, besides thirty-five State Organizing Secretaries, with effect from 18th of December, 2014:

1. State President & Convenor: M. P. Kumar, Southern railway, Chennai

2. State General Secretary & PR, Media Co-ordinator : S. Karuppaiah Madras Fertilizers Ltd., Manali, Chennai-68

3. Working President, (a) G. Srinivasan CVRDE, Defence, Avadi, Chennai-54

4. State Treasurer: J. P. Nagapushanam, Editor, Janapatrik & Dalit Welfare Trust, No. 01, Lane Street, Annasalai, Chennai-02.

5. Asst Treasurer : C. Ashok Kumar, OCF, Defence, Avadi, Chennai

6. Vice Presidents : (1) D. Ravichandran, OCF, Defence, Avadi, Chennai-54

(2) M. Kumaravel, Postal Department, Chennai

(3) E. Thiyagarajan, Food Corporation of India, Chennai

(4) M Mathiparayanar, Dr. Ambedkar Makkal Padai, Medical Store, Periyamet, Chennai

All India Confederation of SC/ST Organizations came into being in October, 1997 to get anti reservation orders dated 30/01/1997, 02/07/1997, 22/07/1997, 13/08/1997 and 29/08/1997 repealed. Due to its vibrant struggle, the government made 81st, 82nd and 85th amendments in the Constitution of India and reservations were protected. The main aim of the Confederation is to build a society which can achieve a strong and happy nation. Most of the Government of India, State government and public sector departments have already recognized the existence of this Confederation and have assured to extend their continued support in the future. There are over one thousand Associations of SC/ST employees working in various State and Central Government departments and public sector undertakings and social workers throughout the country as well as social workers. Article 19 (e) of Constitution of India provides right to form Associations and Unions and to bring grievances of members of these Associations at State and District levels and people in general to the notice of concerned Departments of the Government for redressal of their genuine grievances. To strengthen the hands of Government, the Confederation has been doing welfare activities within the purview of the Constitution since its very inception. +++

25 lakh vs thousands

New Delhi, 8th Dec, 2014: While speaking in the Rally, held on 8th December, 2014, at Ram Lila Maidan, New Delhi, Dr. Udit Raj, National Chairman, All India Confederation of SC/ST Federations, asked a large audience categorically that whether 25 lakh employees and officers who are well-educated and having secure career can better fight for the society or about one thousand MPs and MLAs. These MLAs and MPs or for that matter SC/ST political workers in different political parties depend on upper caste leaders who dictate what has to be done. In such circumstances, how can you leave the responsibility to politicians to empower the society, and high expectation is like day-dreaming. It is not that all politicians are betrayers and selfish but they know their limitations. If they try to assert they have to face consequences. It is the party which arranges finance, voters and workers and disobeying the dictates of the party tantamount to denial of these facilities. In absence of these privileges, politicians lose their strength and the same Dalit society does not guarantee any kind of security and protection to promote them. It is very horrifying and humiliating to them as no one cares. Unlike other society, ours is a different which is selfish and coward. If upper caste politicians are humiliated and betrayed, their caste herd comes out on road and speaks and protests but do we ever witness in case of Dalits and tribals? Not only SC/ST political activities are neglected by upper caste dominated party and politicians but they are deserted by their own people. However, it does not mean that SC/ST political activists are paying back to society what is expected of them. A few try to discharge their responsibility but due to insecurity and the lack of knowledge, they are crippled.

The number of SC/ST employees must be around 25 lakh in the country and they are equipped with knowledge and having job security till the age of sixty, who else can be better than these two better pay back to society. The number is also very high to encompass the vast society. They have money, talent and time to give right direction to the society. The All India Confederation of SC/ST Organizations believes in it and it has empirical basis. It was these employees who struggled for cancellation of anti-reservation orders. If any employee pretexts that he cannot do so, it is simply cheating as has been proved. If the message of social justice could spread fast in northern India after the eighties, the role was played by employees. So now the time has come that lakhs of employees come out and awaken the society. There is no risk in doing so as it is a smooth process. What they have to do is to share their mind and money, and that will awaken sleeping people. Ours is a huge society, and uniting them with right consciousness will take care of our dignity, right and share in governance.

+++

Jammu & Kashmir Confederation Unit reconstitutes its State unit

JAMMU, 30th Dec, 2014: All India Confederation of SC/ST/OBC Organisations(J&K) today reconstituted its State unit in a meeting held at its office to further strengthen the ongoing struggle for upliftment of SC/ST/OBCs of the State. Mr. R. K. Kalsotra, President of the State Unit nominated following enrolled members as office bearers of the State Unit- Darshan Bhagat, Mustaq Badgami, Ramesh Sarmal, Parveen Jaryal and Ashaq Ali Watal as Vice Presidents; Rohit Verma and B L Bhardwaj as General Secretaries; Ramesh Kaith, Krishna Bangotra, Shabnam Gureji, Haji Ahsan Ali Gonkapa, and Tsering Morup as Joint Secretaries; Hardutt Saryara and Nazir Ahmed Khattana as Organising Secretaries; Mohinder Kumar and Mehraj-Ud-Din Khattana as Public Secretaries, and Harbans Lal Loach as a Treasurer. Mr. Kalsotra clarified that further expansion of office bearers will be carried out in the near future to fortify the cause which the Confederation is pursuing. The President gave a call to the entire cadre to participate in the Dignity & Rights Maharally to be held at Ramlila Maidan, New Delhi on 08 December, 2014 to demand passing of 117th Constitutional Amendment to provide Reservation in Promotion, Reservation in private Sector & Judiciary, Ban Contract System in Safai Work, Fill up backlog posts by special drive, Right to Equal Opportunity of Education, Land to the Landless & Tiller, Enact Reservation Act, Legislation to SCP/TSP/OBC, Caste Certificate of one State should be valid in other States, Raise Scholarship amount as per Price Index, Stop dilution of ST Status, Political Reservation to ST and implement in toto Mandal Commission Report in J&K.

+++

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 18 ● Issue 3 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 16 to 31 December, 2014

Lakhs of Dalits demonstrates their strength at Ramlila Ground, New Delhi

C. L. Maurya

New Delhi, 8th December, 2014 : Today, lakhs of SC/ST employees and social activists under the banner of All India Confederation of SC/ST Organizations assembled at Ramlila Ground, New Delhi from 10 AM onwards where the crowd started pouring in right from the day break. Confederation's Chairman, Dr. Udit Raj welcomed them and thanked for coming to the Rally from all corners of the country with high hopes that outstanding demands of the Dalits will be heard and considered by the government.

Dr. Udit Raj exhorted employees and social activists that they are to fight for their rights. They should not consider themselves other than political representatives in so far as serving Dalits and Adivasis is concerned. In other words, SC/ST employees represent these people as politicians do. Dr. B.R. Ambedkar had hoped more from educated people to struggle for justice. This is the 17th Rally of All India Confederation of SC/ST Organizations and is the largest socio-economic organization in the country. It is the organization with a difference which always engages constructive work rather than accusing the upper castes. Because of this approach, the Confederation has positioned itself to add many rights for the Dalits. It was only due to the struggle of Confederation only that Vajpayee-led Government made 81st, 82nd, and 85th Constitutional amendments. Not only service related grievances of SC/ST employees are taken up by us on day- to-day basis but atrocities cases also. Confederation made private sector reservation a popular agenda.

This time there is much more enthusiasm in the rank and file, as the new government has portrayed high hopes for us. This is a well-known fact that in six months of functioning of the government not much can be expected. When UPA came in to power in 2004, it moved fast to introduce a bill to enact Reservation Act in 2004. The bill was passed in 2009 but when deficiency was noticed, the government withdrew it with the promise to reintroduce it but it remained mirage even in second tenure of the government. We hope that this government will pass it.

Another bill to remove the bottlenecks in promotion was introduced in Rajya Sabha in 2012 but got stuck in Lok Sabha and there should not be any difficulty to meet this demand also. There are a lot of anomalies and confusion in implementing reservation. Recently, Punjab and Haryana High Courts has delivered a decision which has tremendous negative impact on reservation in promotions for SC/ST employees and now they are being reverted. To strengthen the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, a bill is pending in the Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment which can be easily passed. Recently a mega survey was conducted by National Council of Applied Economic Research (NCAER) and the University of Maryland, US which revealed that still one/fourth of Indian population is subjected to the age-old concept of untouchability. In addition to these grievances, contract system is playing havoc and therefore it should be banned. There are a very few recruitments in the government departments and to meet the requirements of teachers, doctors, nurses, assistants, peons etc., they are recruited either on ad-hoc or temporary basis where no reservation system is followed, thus denying opportunities to SC/ST candidates. For a bulk of these employees comprising thirty to forty percent of the total workforce, there is complete denial of reservation. When after a certain interval they are going to be regularized, SC/ST candidates are not considered, because they don't have working experience. And hence they are suffering from double jeopardy. We urge upon the government that it should apply reservation for temporary and contractual recruitment. The caste certificate of one State should be valid in other States.

The UPA government set up three committees to explore all possibilities to provide reservation in private sector and that finally did not come through and a compromise formula was worked out with all major industrial associations that they will work for SC/ST in various fields like education, entrepreneurship and jobs. However, the corporate houses came forward to do welfare for SC/STs through other instruments like imparting tuitions, physical training and preparing entrepreneurs but there is hardly any visible result. These communities are totally excluded from mainstreams like capital markets, industries, IT, service sector, private education, film, journalism, export-import, land etc. and it has a bearing not only on the lives of these communities but unity and integrity of the country. How can a nation progress when such a large population is kept out of the mainstream? If such a large section of well-educated population is kept out of the main stream development process, it is fraught with the danger of these educated youths swaying away from the mainstream society. Even advance countries like USA have policy of affirmative action, which is not only equal to reservation but more than that. Deprived people over there do not get opportunity in government sectors only but in private sector as well.

+++

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com
Computer typesetting by C. L. Maurya